International Journal of Management, IT & Engineering
Vol. 8 Issue 4, April 2018, ISSN: 2249-0558
Impact Factor: 7.119Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत में कृषि के मुद्दों और प्राथमिकताओं पर एक नूतन विमर्श

अनिल कुमार यादव
प्रवक्ता (भूगोल)
आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज ककरही गोरखपुर

सारांश

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्रबिंदु है और भारतीय जीवन की धुरी है। आर्थिक जीवन का आधार, रोजगार का मुख्य स्रोत और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा जाए तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52 प्रतिशत कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों से अपनी आजीविका कमा रहा है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि देश का विकास और समृद्धि कृषि के विकास, समृद्धि और उत्पादकता पर ही निर्भर करती है। कृषि का विकास और समृद्धि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादित उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने पर निर्भर है। गौरतलब है कि देश के ज्यादातर छोटे किसान गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। गरीबी और कर्ज के कारण किसान बिचौलियों को कम कीमत पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं। किसानों को इन बिचौलियों के जाल से मुक्त करने और विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने नियंत्रित मंडियों का विस्तार, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग और प्रभाव, गोदामों की व्यवस्था, बाजार का प्रचार-प्रसार और मूल्य संबंधी जानकारी जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संस्थान कृषि विपणन में विशेष शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान सेवाएं प्रदान कर कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की उच्च विकास दर के कारण कम होकर 15% से कम हो गई है, भारत के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने में इस क्षेत्र का महत्व इस सूचक से बहुत आगे जाता है। पहला, भारत के लगभग तीन-चौथाई परिवार ग्रामीण आय पर निर्भर हैं। दूसरा, भारत के अधिकांश गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और तीसरा, भारत की खाद्य सुरक्षा अनाज की फसलों के उत्पादन के साथ-साथ बढ़ती आय के साथ बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए फलों, सब्जियों और दूध के उत्पादन में वृद्धि पर निर्भर करती है।

मूल शब्द: कृषि विपणन, भारतीय अर्थव्यवस्था, श्रम शक्ति, कृषि का विकास, खाद्य सुरक्षा

प्रस्तावना

भारत एक वैश्विक कृषि महाशक्ति है। यह दूध, दालों और मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, मछली, भेड़ और बकरी का मांस, फल, सब्जियां और चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में लगभग 195 मिलियन हेक्टेयर की खेती की जाती है, जिसमें से कुछ 63 प्रतिशत वर्षा

(लगभग 125 मिलियन हेक्टेयर) पर निर्भर हैं, जबकि 37 प्रतिशत सिंचित (70 मिलियन हेक्टेयर) हैं। भारत के समग्र विकास और इसके ग्रामीण गरीबों के बेहतर कल्याण के लिए कृषि क्षेत्र की तीन चुनौतियाँ महत्वपूर्ण हैं।

1. भूमि की प्रति इकाई कृषि उत्पादकता बढ़ाना: प्रति इकाई भूमि की उत्पादकता बढ़ाना कृषि विकास का मुख्य इंजन होना चाहिए क्योंकि लगभग सभी कृषि योग्य भूमि पर खेती की जाती है। जल संसाधन भी सीमित हैं और सिंचाई के लिए पानी को बढ़ती औद्योगिक और शहरी जरूरतों के साथ संघर्ष करना चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने के लिए सभी उपायों का दोहन करने की आवश्यकता होगी, उनमें से पैदावार बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों का विविधीकरण, और विपणन लागत को कम करने के लिए मूल्य श्रृंखला विकसित करना।

2. सामाजिक रूप से समावेशी रणनीति के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करना जिसमें कृषि और गैर-कृषि रोजगार दोनों शामिल हैं। ग्रामीण विकास से गरीबों, भूमिहीनों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी लाभ होना चाहिए। इसके अलावा, मजबूत क्षेत्रीय असमानताएं हैं। भारत के अधिकांश गरीब वर्षा आधारित क्षेत्रों में या पूर्वी भारत-गंगा के मैदानों में हैं। ऐसे समूहों तक पहुंचना आसान नहीं होता। जबकि प्रगति हुई है - गरीब के रूप में वर्गीकृत ग्रामीण आबादी 1990 के दशक की शुरुआत में लगभग 40% से गिरकर 2000 के दशक के मध्य तक 30% से कम हो गई (प्रति वर्ष लगभग 1% की गिरावट)। इसलिए, गरीबी उन्मूलन सरकार और विश्व बैंक के ग्रामीण विकास प्रयासों का एक केंद्रीय स्तंभ है।

3. यह सुनिश्चित करना कि कृषि विकास खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हो। 1970 के दशक की भारत की हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में तेज वृद्धि ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और अकाल के खतरे को दूर करने में सक्षम बनाया। 1970 से 1980 के दशक में कृषि गहनता ने ग्रामीण श्रम की मांग में वृद्धि देखी जिसने ग्रामीण मजदूरी को बढ़ाया और खाद्य कीमतों में गिरावट के साथ-साथ ग्रामीण गरीबी को कम किया। हालाँकि 1990 और 2000 के दशक में कृषि विकास धीमा हो गया, औसतन लगभग 3.5% प्रति वर्ष, और अनाज की पैदावार में 2000 के दशक में केवल 1.4% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। कृषि विकास में मंदी चिंता का एक प्रमुख कारण बन गई है। भारत की चावल की पैदावार चीन की एक तिहाई और वियतनाम और इंडोनेशिया में लगभग आधी है। अधिकांश अन्य कृषि जिंसों का भी यही हाल है।

इस प्रकार नीति निर्माताओं को इस क्षेत्र को मौजूदा नीति और संस्थागत शासन से दूर स्थानांतरित करने के लिए नीतिगत कार्रवाइयों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को शुरू करने और/या समाप्त करने की आवश्यकता होगी जो अब व्यवहार्य नहीं है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

1. कृषि उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और ग्रामीण विकास को बढ़ाना

- नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और कृषि अनुसंधान और विस्तार में सुधार:- भारत के कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रणालियों का प्रमुख सुधार और सुदृढ़ीकरण कृषि विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। इन सेवाओं में समय के साथ बुनियादी ढांचे और संचालन की पुरानी कमी, या अत्याधुनिक तकनीकों तक व्यापक पहुंच के कारण गिरावट आई है। सार्वजनिक विस्तार

सेवाएं संघर्ष कर रही हैं और किसानों को थोड़ा नया ज्ञान प्रदान करती हैं। अनुसंधान और विस्तार, या इन सेवाओं और निजी क्षेत्र के बीच बहुत कम संबंध है।

- जल संसाधन और सिंचाई/जल निकासी प्रबंधन में सुधार:- कृषि भारत में पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। हालांकि, उद्योग, घरेलू उपयोग और कृषि के बीच पानी के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने नदी बेसिन और बहु-क्षेत्रीय आधार पर पानी की योजना और प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। जैसे-जैसे शहरी और अन्य मांगें बढ़ती हैं, सिंचाई के लिए कम पानी उपलब्ध होने की संभावना है। सिंचाई की उत्पादकता को मौलिक रूप से बढ़ाने के तरीके ("प्रति बूंद अधिक फसल") खोजने की जरूरत है। भूजल के दोहन के बजाय प्रबंधन करने की भी जरूरत है। कम पानी पंप करने के लिए प्रोत्साहन जैसे बिजली शुल्क लगाना या उपयोग की सामुदायिक निगरानी अभी तक छिटपुट पहल से आगे नहीं बढ़ पाई है। अन्य प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं: (i) सिंचाई के पानी के प्रबंधन में किसानों और अन्य एजेंसियों की भागीदारी को एकीकृत करने के लिए सिंचाई और जल निकासी विभागों का आधुनिकीकरण; (ii) लागत वसूली में सुधार; (iii) उच्चतम रिटर्न वाली योजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के साथ सार्वजनिक व्यय को युक्तिसंगत बनाना; और (iv) निवेश की स्थिरता के लिए संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करना।
- उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए कृषि विविधीकरण की सुविधा:- किसानों को उच्च मूल्य की वस्तुओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना उच्च कृषि विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगा, विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में जहां गरीबी अधिक है। इसके अलावा, कृषि-प्रसंस्करण के विस्तार और उत्पादकों से शहरी केंद्रों और निर्यात बाजारों तक प्रतिस्पर्धी मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए काफी संभावनाएं मौजूद हैं। जबकि विविधीकरण की पहल किसानों और उद्यमियों पर छोड़ दी जानी चाहिए। सरकार, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, विपणन, परिवहन, निर्यात और प्रसंस्करण के लिए बाधाओं को उदार बना सकती है। यह एक छोटी नियामक भूमिका भी निभा सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि यह एक बाधा न बने।
- उच्च वृद्धि वाली वस्तुओं को बढ़ावा देना:- कुछ कृषि उप-क्षेत्रों में विशेष रूप से डेयरी के विस्तार की उच्च संभावनाएं हैं। पशुधन क्षेत्र, मुख्य रूप से डेयरी के कारण, कृषि सकल घरेलू उत्पाद का एक चौथाई से अधिक योगदान देता है और भारत के ग्रामीण परिवारों के 70% के लिए आय का एक स्रोत है, ज्यादातर वे जो गरीब हैं और महिलाओं के नेतृत्व में हैं। दुग्ध उत्पादन में लगभग 4% प्रति वर्ष की वृद्धि तेज रही है, लेकिन भविष्य में घरेलू मांग में कम से कम 5% प्रति वर्ष की वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि, गायों की खराब आनुवंशिक गुणवत्ता, अपर्याप्त पोषक तत्व, दुर्गम पशु चिकित्सा देखभाल और अन्य कारकों से दूध उत्पादन बाधित होता है। इन बाधाओं से निपटने के लिए एक लक्षित कार्यक्रम उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है और गरीबी काम करने में अच्छा प्रभाव डाल सकता है।

- विकासशील बाजार, कृषि ऋण और सार्वजनिक व्यय:- कृषि विपणन में व्यापक सरकारी भागीदारी की भारत की विरासत ने आंतरिक और बाहरी व्यापार में प्रतिबंध पैदा कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि वस्तुओं के लिए बोझिल और उच्च लागत वाले विपणन और परिवहन विकल्प हैं। फिर भी, विपणन, मूल्य श्रृंखला और कृषि-प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ रहा है, लेकिन क्षमता से बहुत धीमा है। जबकि कुछ प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, विविधीकरण को सक्षम करने और उपभोक्ता कीमतों को कम करने के लिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए ग्रामीण वित्त तक पहुंच में सुधार करना एक और आवश्यकता है क्योंकि किसानों के लिए ऋण प्राप्त करना मुश्किल है। इसके अलावा, बिजली, उर्वरक और सिंचाई पर सब्सिडी सरकारी खर्चों पर उत्तरोत्तर हावी हो गई है, और अब यह निवेश व्यय से चार गुना अधिक है, कृषि अनुसंधान और विस्तार जैसी शीर्ष प्राथमिकताओं को खत्म कर रही है।

2. गरीबी उपशमन और सामुदायिक कार्य

जबकि कृषि विकास, अपने आप में, 170 मिलियन या उससे अधिक ग्रामीण व्यक्तियों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, आय बढ़ाने के लिए आधार प्रदान करेगा, इस विकास को समावेशी बनाने के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एक ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम जो समुदायों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाता है, विशेष रूप से प्रभावी और स्केलिंग-अप के लिए उपयुक्त पाया गया है। यह कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा देता है, सामुदायिक बचत को बढ़ाता है, और आय और रोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय पहल को बढ़ावा देता है। बड़े निकाय बनने के लिए संघ द्वारा, गरीबों की ये संस्थाएं अपने उत्पादों के लिए बेहतर कीमतों और बाजार पहुंच के लिए बातचीत करने की ताकत हासिल करती हैं, और स्थानीय सरकारों पर उन्हें बेहतर तकनीकी और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए राजनीतिक शक्ति भी हासिल करती हैं। ये स्वयं सहायता समूह महिलाओं और गरीब परिवारों तक पहुंचने में विशेष रूप से प्रभावी हैं।

3. पर्यावरण और भविष्य की कृषि उत्पादकता को बनाए रखना

भारत के कुछ हिस्सों में, कृषि उपयोग के लिए पानी के अत्यधिक पंपिंग से भूजल स्तर गिर रहा है। इसके विपरीत, जल-जमाव के कारण कुछ सिंचित क्षेत्रों की मिट्टी में लवणों का निर्माण हो रहा है। दूसरी ओर, वर्षा आधारित क्षेत्रों में, जहां अधिकांश ग्रामीण आबादी रहती है, मिट्टी के कटाव को कम करने और वर्षा के अवशोषण को बढ़ाने के लिए कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। इन सभी समस्याओं के लगभग सिद्ध समाधान हैं। वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे व्यापक है, जहां समुदाय भूमि नियोजन में संलग्न होते हैं और कृषि प्रथाओं को अपनाते हैं जो मिट्टी की रक्षा करते हैं, जल अवशोषण बढ़ाते हैं और उच्च पैदावार और फसल विविधीकरण के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाते हैं। हालांकि, मुद्दा यह है कि देश के बड़े क्षेत्रों को कवर करने के लिए इस तरह की पहल को कैसे बढ़ाया जाए। जलवायु परिवर्तन पर भी विचार किया जाना चाहिए। सूखा, बाढ़, अनिश्चित बारिश - अपेक्षित हैं और वर्षा आधारित क्षेत्रों में इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। वाटरशेड कार्यक्रम, कृषि अनुसंधान और विस्तार की पहल से संबद्ध, फसलों की नई किस्मों और उन्नत

कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त कृषि कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन आजीविका कार्यक्रम और गैर-कृषि रोजगार का विकास भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

विश्व बैंक सहायता

भारत में विश्व बैंक का कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पूर्ण डॉलर के संदर्भ में दुनिया भर में बैंक का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है। यह आंकड़ा और भी अधिक है जब ग्रामीण विकास जैसे ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण वित्त और मानव विकास में निवेश को शामिल किया जाता है। फिर भी, कृषि के समर्थन में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकार के वित्त पोषण की तुलना में यह राशि अपेक्षाकृत कम है। बैंक की अधिकांश कृषि और ग्रामीण विकास सहायता राज्य-स्तरीय सहायता के लिए तैयार की जाती है, लेकिन कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है।

- भारत सरकार की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा समन्वित अखिल भारतीय कार्यान्वयन (राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना और राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना) के साथ दो राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं के माध्यम से कृषि प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास।
- कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार:- कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार की दिशा में नए दृष्टिकोण जैसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) मॉडल ने असम और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के विविधीकरण में योगदान दिया है। इस विस्तार दृष्टिकोण को अब पूरे भारत में बढ़ाया जा रहा है।
- सिंचाई के पानी की बेहतर डिलीवरी:- सिंचाई के पानी की बेहतर डिलीवरी के लिए विश्व बैंक का समर्थन, बड़े सिंचाई बुनियादी ढांचे को कवर करने वाली परियोजनाओं से लेकर स्थानीय टैंकों और तालाबों तक। परियोजनाएं कई राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश) में जल संस्थानों के सुदृढ़ीकरण का समर्थन करती हैं, भूजल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार (उदाहरण के लिए, आगामी राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना में)।
- वाटरशेड और वर्षा आधारित कृषि विकास (कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), मृदा सुधार प्रयासों (उत्तर प्रदेश) और हाल ही में, बेहतर भूजल प्रबंधन प्रथाओं (उदाहरण के लिए, आगामी राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना में) के माध्यम से सतत कृषि पद्धतियां।
- कई राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु) द्वारा शुरू की गई ग्रामीण आजीविका पहलों के माध्यम से ग्रामीण ऋण तक बेहतर पहुंच और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में अधिक से अधिक लैंगिक भागीदारी और जल्द ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से बैंक समर्थन के साथ भारत सरकार द्वारा इसे बढ़ाया जाएगा
- बीमा कार्यक्रम के बीमांकिक डिजाइन और कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए भारत सरकार को सलाह देकर कृषि बीमा (जैसे रेटिंग पद्धति और उत्पाद डिजाइन, सूचकांक बीमा, उपज मापने के लिए मोबाइल और रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग, आदि)।

- महाराष्ट्र कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना के तहत नीतिगत सुधारों और निवेशों के माध्यम से कृषि बाजारों तक किसानों की पहुंच में सुधार, जिसका उद्देश्य विनियमित थोक बाजारों में सुधार करना और किसानों को वैकल्पिक बाजार के अवसर प्रदान करना है।
- भारत सरकार के राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के समर्थन में विश्लेषणात्मक कार्य के साथ-साथ गैर-उधार तकनीकी सहायता के माध्यम से भूमि नीति एजेंडा।
- प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (पीएमजीएसवाई) को आईडीए समर्थन के माध्यम से बेहतर ग्रामीण संपर्क, और ग्रामीण गरीब और छोटे किसानों को सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (और एसएचजी संघों), जल उपयोगकर्ता संघों और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं से जोड़कर हाल ही में बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को मंजूरी दी, जो अखिल भारतीय दृष्टिकोण के माध्यम से एसएचजी दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

किसानों की कुल आमदनी का एक हिस्सा ही अब खेती से आता है और बाकी आमदनी मजदूरी, गैर कृषि गतिविधियां और अन्य जरिये से होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि छोटे किसान सबसे ज्यादा मार्केट और उत्पाद कीमतों में उतार-चढ़ाव का जोखिम झेलते हैं और इससे निबटने के लिए सांस्थानिक मशीनरी गायब है। उत्पाद की कीमत का निर्धारण अब भी एपीएमसी मार्केट करता है जो कायदे से विनियमित नहीं है और कई मामलों में किसानों के साथ दुर्व्यवहार करता है। सरकारी एजेंसियों का मुख्य कार्य सुधारों की व्यापक स्वीकृति के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके लिए तीन चीजों- जानकारी, बुद्धिमता और पारस्परिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। प्रखर प्रणालियों के माध्यम से एकत्रकी गई सही जानकारी को हितधारकों के सामने रखा जाना चाहिए जिससे किसी किस्से-कहानियों पर आधारित कोई निर्णय की बजाय बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया जा सके। भारतीय किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और कीमत के लिए विश्व-स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उद्यमी निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर कृषि के लिए और कृषि में निवेश के लिए मुख्यधारा में लाना चाहिए। कृषि अनुसन्धान एवं विकास क्षेत्र में नूतन प्रयोग करने की आवश्यकता है जिससे सूक्ष्म कृषि, उच्च पोषक और प्रसंस्कृत किए जाने वाली किस्में, जलवायु प्रतिरोधक प्रौद्योगिकियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि और बाजार परामर्शों के लिए साइबर कृषि भौतिक प्रणालियाँ विकसित हो सकें।

References

- World Bank. (2012). India: issues and priorities for agriculture. *World Bank News*.
- Mohan, R. (2006). Agricultural credit in India: Status, issues and future agenda. *Economic and Political Weekly*, 1013-1023.
- Sen, A. (1992). Economic liberalisation and agriculture in India. *Social Scientist*, 4-19.

- Bhatt, B. P., Meena, M. S., & Singh, K. M. (2013). Status and issues of agriculture in Eastern India. *Souvenir released during Agri-Summit*, 8-9.
- Reddy, Y. V. (2001). Indian Agriculture and Reform: Concerns, Issues and Agenda. *Indian journal of agricultural marketing*, *15*(1), 1-9.
- World Bank. (2012). India: issues and priorities for agriculture. *World Bank News*.
- Rao, C. H., & Gulati, A. (1994). Indian agriculture: Emerging perspectives and policy issues. *Economic and Political Weekly*, A158-A169.
- Atkinson, J., Scurrah, M., Lingán, J., Pizarro, R., & Ross, C. (2009). Case Study: Trade and Agriculture in India. In *Globalizing Social Justice* (pp. 94-117). Palgrave Macmillan, London.
- Parthasarathy, G. (2001). Modernising Indian Agriculture: Priority Tasks and Critical Policies. *Indian Journal of Agricultural Economics*, *56*(4), 743.
- Singh, T. (2017). Issues and Challenges of Indian Agriculture. *International Journal of Research in Social Sciences*, *7*(9), 727-736.
- Singh, T. (1989). Agriculture and rural poverty: issues re-examined. *Economic Problems of Modern India: Problems of Development*, *1*, 216.
- Hanumantha Rao, C. H. (1995). Liberalisation of agriculture in India: Some major issues. *Indian Journal of Agricultural Economics*, *50*(902-2018-3384), 468-472.
- Kalirajan, K. P., & Sankar, U. (2001). Agriculture in India's economic reform program. *Journal of Asian Economics*, *12*(3), 383-399.
- Gautam, M. (2016). Making Indian agriculture more resilient: Some policy priorities. *Economic and Political Weekly*, 24-27.